

अनूप गवावन,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
शहरी विकास विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून दिनांक- 04 जनरी 2010  
दिनांक- 0000

विषय : नगर पंचायत, कर्णप्रयाग के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि से वित्तीय वर्ष-2008-08 में स्वीकृत निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किस्ता चालू वित्तीय वर्ष 2008-10 में स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं० 470/V-शावि-08-45(सा0)/08 दिनांक 8-3-2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर पंचायत, कर्णप्रयाग के अन्तर्गत रु० 74.39 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कराते हुए रु० 33.01 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कर्णप्रयाग के पत्र संख्या 364/अवस्थापना विकास निधि/2008-08 दिनांक 13-2-2008 के माध्यम से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र में न्यूनतम निविदा के सापेक्ष हुई बयत की धनराशि रु० 0.08 लाख के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 8-3-2008 के माध्यम से स्वीकृत कार्य के लिए स्वीकृति हेतु अवशेष रु० 41.38 लाख में से न्यूनतम निविदा के सापेक्ष हुई बयत की धनराशि रु० 0.08 लाख का समायोजन कराते हुए स्वीकृति हेतु अब अवशेष रु० 41.30 लाख के सापेक्ष रहनेवाले वित्तीय वर्ष से रु०-24.17 लाख (रुपये चौबीस लाख सतरह हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके नियंत्रण पर विम्बलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. उक्त धनराशि रु०-24.17 लाख (रुपये चौबीस लाख सतरह हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर सम्बन्धित नगर पंचायत को बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी, जो शासनादेश की शर्त पूर्ण करने पर कार्यदायी संस्था को अद्युक्त करेंगे।
2. शासनादेश संख्या 470/V-शावि-08-45(सा0)/08 दिनांक 8-3-2008 में उल्लिखित अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगमनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
4. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।
5. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुरितका, बजट मैन्युअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
6. कार्य के मध्य तथा बाद में इसकी गुणवत्ता की चेंकिंग, किसी तृतीय तकनीकी पक्ष से कराके उसकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित किया जायेगा और इसका खर्च योजना की अनुमोदित लागत से ही वहन किया जायेगा।
7. सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं तो सम्बन्धित संस्था को अग्रोत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।
8. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

9. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जावे तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
  10. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनोद्देश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगमन गति करत समय का कड़ाई से पालन किया जाए।
  11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-3-2010 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
  12. अपर बाजार में पार्किंग स्थल के निर्माण कार्य की पूर्ण निविदा कर, न्यूनतम निविदा के सापेक्ष हुई बचत सहित अन्तिम किस्त अवमुक्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त आगामी किस्त अवमुक्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।
  13. यदि कार्य की लागत स्वीकृत धनराशि से अधिक आती है तो अतिरिक्त लागत को नगर पंचायत द्वारा अपनी निधि से वहन किया जायेगा।
  14. अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत अद्यतन तिथि तक प्राप्त ब्याज की धनराशि को तत्काल राजकोष में जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रति शासन तथा शहरी विकास निदेशालय को अविलम्ब उपलब्ध करायी जायेगी।
- 2- उक्त के संकेत में होने वाला वार्षिक वित्तीय वर्ष 2008-10 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत महा के लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-19-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05- नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद '20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता' के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग को अशा0सं0- 562/XXVII(2)/2009, दिनांक- 18 दिसम्बर, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनूप कथावन)  
सचिव।

सं० 1880 (1)/IV(2)-सचि०-09, तदुदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल भण्डल, पीडी।
6. जिलाधिकारी, घमोली।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. चित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी०ओ० में इसे शामिल करें।
10. अध्यक्ष/अधिकांशी अधिकारी, नगर पंचायत, कर्णप्रवाह।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. मार्क बुक।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)  
अनु सचिव।